Title: Demand to provide more powers to the MLA(s)/MP(s) to check the bureaucracy and to bring back illegal amount deposited in the Swiss Banks.

श्रीमती कैलाशो देवी (कुरूक्षेत्र): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहती हूं कि विकास कार्यों के लिए विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सरकार की तरफ से जो पैसा दिया जाता है, जिसमें एम.पीज. और एम.एल.एज. की ग्रांट को भी शामिल किया जा सकता है, उसका १० प्रतिशत पैसा भी विकास कार्यों पर नहीं लग पाता है। उसे बिचौलिये हजम कर जाते हैं।

यदि कोई काम सही ढंग से नहीं होता, देर से होता है या फिर उसमें विकास कार्यों पर सामान सही और उचित क्वालिटी का नहीं लग पाता है तो उसके लिए पब्लिक जनप्रतिनिधियों से आकर कहती है। उसके लिए जवाबदेह जनप्रतिनिधि हैं, जबकि सारी वित्तीय, कार्यकारी एवं प्रशासकीय शक्तियां ब्यूरोक्रेटस के पास हैं। यदि कोई डिप्टी कमिश्नर किसी एम.पी. के कहने से जनहित के जायज कामों में भी रोड़ा अटकाता है और बार-बार कहने के बावजूद भी काम नहीं करता है तो किसी एम.पी. के पास उसके खिलाफ क्या पावर्स हैं, वह उसके खिलाफ क्या एक्शन ले सकता है? सरकार यह बताये कि एम.पी. की ये शक्तियां हैं, वह यह कर सकता है।

मैं दो मिनट में एक बात और कहना चाहती हूं। एम.पी. केवल शिकायत कर सकता है, लेकिन उस शिकायत पर कार्रवाई होने में महीनों लग जाते हैं। इससे इन ब्यूरोक्रेटस का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ जाता है, उनके हौसले बुलन्द हो जाते हैं। जनप्रतिनिधियों को वित्तीय, प्रशासकीय और कार्यकारी अधिकार न मिल पाने के कारण उनके हाथ-पांव कटे होते हैं। संविधान में संशोधन करके यह कानून बनाया जाये कि एम.एल.ए. या एम.पी. की ये शक्तियां हैं, ये पावर्स हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : भारत सरकार को इसमें क्या करना चाहिए, आप वह बताइये।

श्रीमती कैलाशो देवी : भारत सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए कि एम.पीज़. की ये पावर्स हैं। जब तक पावर्स निश्चित नहीं की जाएंगी, तब तक प्रजातंत्र के ऊपर ब्यूरोक्रेसी इसी प्रकार हावी रहेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात पूरी नहीं कर पाई हूं, मुझे एक मिनट का समय और दे दें। प्रधान मंत्री जी ने कुछ दिन पूर्व यह कहा था कि ब्यूरोक्रेसी कार्यों में अड़चन डालती है, उस सम्बन्ध में सरकार ने क्या नियम बनाये हैं? प्रधान मंत्री जी ने क्या कोई सकारात्मक कदम उठाये हैं? प्रधान मंत्री जी का एक बयान भी अखबारों में प्रकाशित हुआ था कि स्विस प्रधान मंत्री ने फोन पर उनसे कहा है कि हिन्दुस्तान के भ्रष्ट लोगों का बेइंतहा पैसा स्विस बैंकों में जमा पड़ा है। क्या सरकार ने उस पैसे को भारत में लाने के लिए कोई पहल की है, कोई सकारात्मक कदम उठाया है, ताकि बड़ी-बड़ी विकास की परियोजनाएं, बड़े-बड़े डैम्स, पावर प्लांटस, रिफाइनरीज़, जो लम्बे समय से लम्बित पड़े हैं, उनको पूरा किया जा सके। हिन्दुस्तान में गरीबी, बेरोजगारी और भुखमरी को जड़ से उखाड़कर फेंका जा सके। सरकार इस बारे में पहल क्यों नहीं कर रही है?